जोधन

बनाम

एम.पी. राज्य

2010 की आपराधिक अपील संख्या 1683

अप्रैल 08,2015

[न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एन. वी. रमना]

दंड संहिता, 1860: धारा 302, 323, 324 सपठित 149–अभियोजन पक्ष का कहना था कि आरोपियों ने मृतक और शिकायतकर्ता पक्ष पर लाठी, फरसा और बम से हमला किया–विचारण न्यायालय ने अभियोजन की कहानी पर विश्वास नहीं किया और आरोपी को बरी कर दिया–उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि–दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील– माना गया: अभियोजन पक्ष न केवल अपीलकर्ता की उपस्थिति स्थापित करने में सक्षम था, बल्कि गैरकानूनी सभा के सदस्य के रूप में उसकी सक्रिय भागीदारी भी स्थापित करने में सक्षम था–यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सबूत थे कि सभी आरोपी व्यक्तियों ने एक गैरकानूनी सभा का गठन किया था और मृतक पर हमला करना उनका सामान्य उद्देश्य था, जिसने खुद को लगी चोटों के कारण दम तोड़ दिया– विचारण न्यायाधीश–विचारण न्यायाधीश का यह मानना था की यह एक खुली लड़ाई थी–उक्त निष्कर्ष स्पष्ट रूप से गलत था क्योंकि अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्थापित किया कि आरोपी व्यक्ति हमलावर थे–इस प्रकार, यह ऐसा मामला था जहां अपीलकर्ता धारा 149 की सहायता से धारा 302 के तहत दोषी ठहराए जाने के लायक था–जैसा कि उच्च न्यायालय ने ठीक ही पाया कि गवाह विश्वसनीय थे और अपने कथन पर कायम थे और अडिग रहे–घटना में गवाहों को चोटें आईं–घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी पर संदेह नहीं किया जा सकता–अभियोजन पक्ष के गवाहों, जो घटना के स्वाभाविक गवाह थे, के साक्ष्य में छोटी विसंगतियों और चूक पर जोर देना

और अप्रासंगिक पहलुओं पर जोर देना और अंततः दोषमुक्ति को दर्ज करना, किसी भी कल्पना से इसे विचारण न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किया गया एक प्रशंसनीय या संभावित दृष्टिकोण नहीं माना जा सकता है और इसलिए, एक दोषी को बरी करने के फैसले को पलटना उच्च न्यायालय के लिए उचित था।

अपील: दोषमुक्ति के फैसले के खिलाफ अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय अपीलीय अदालत की शक्ति–का दायरा, चर्चा की गई।

गवाह: घायल गवाह/संबंधित/इच्छुक गवाह–उनकी गवाही की विश्वसनीयता।

अपील खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. पीडब्लू-13 की गवाही और मृतक को लगी चोटों को देखने पर, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि मौत प्रकृति में हत्या थी और विस्फोटक पदार्थ के कारण हुई थी। इस घटना में अन्य गवाहों को भी चोटें आई थीं। पीडब्लू-7, पीडब्लू-14, पीडब्लू-15 और पीडब्लू-16, जो मृतक से संबंधित थे, चश्मदीद गवाह थे और उन्होंने अभियोजन संस्करण का समर्थन किया था। इस प्रस्ताव पर कोई संदेह नहीं हो सकता है कि जब गवाह संबंधित और रुचि रखते हैं, तो उनकी गवाही की बारीकी से जांच की जानी चाहिए, लेकिन मौजूदा मामले में, प्रतिपरिक्षण में उनके संस्करण पर अविश्वास करने के लिए कुछ भी नहीं मिला है। उनके सबूतों की जांच करने पर, यह निश्चितता के साथ कहा जा सकता है कि उन्होंने सभी भौतिक विवरणों में एक-दूसरे के संस्करण का समर्थन किया है। कुछ छोटे-मोटे विरोधाभास और चूकें थीं जिन पर विचारण न्यायाधीश ने जोर दिया। उच्च न्यायालय ने उक्त विसंगतियों और छोटे-मोटे विरोधाभासों को स्वाभाविक माना। इसके अलावा, उनकी गवाही को मेडिकल सबूतों और एफआईआर में लगाए गए शुरुआती आरोपों से भी समर्थन मिला। विचारण न्यायाधीश ने ऐसी चूकों और विरोधाभासों पर अत्यधिक जोर दिया है, जो उच्च न्यायालय के अनुसार, बिल्कुल महत्वहीन और तुच्छ थे। आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ गवाही देने

वाले गवाह करीबी रिश्तेदार थे और घटना में उन्हें चोटें आई थीं। घटना स्थल पर उनकी मौजूदगी पर संदेह नहीं किया जा सकता, उनका बयान सुसंगत था और जिरह में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो उनकी गवाही को हिला सके। कुछ छोटी-मोटी विसंगतियाँ थीं, लेकिन वास्तव में उन्होंने अपने साक्ष्यों में कोई ऐसी गड़बड़ी पैदा नहीं की जिससे उसे असंभव या अविश्वसनीय मान लिया जाए। एक घायल गवाह की गवाही अन्य गवाहों की तुलना में ऊंचे स्थान पर होती है। जहां घटना का गवाह खुद घटना में घायल हो गया हो, ऐसे गवाह की गवाही आम तौर पर बहुत विश्वसनीय मानी जाती है, क्योंकि वह एक ऐसा गवाह है जो अपराध स्थल पर अपनी उपस्थिति की अंतर्निहित आश्वस्ति के साथ आता है और किसी को झूठा फंसाने के लिए अपने वास्तविक हमलावरों को छोड़ देने की संभावना नहीं है। [पैरा 15, 17, 20, 21] [804-ए; 805-ई-एच; 806-ए, बी; 808-ई-एफ; 809-जी; 810-ए-बी]

गामिनी बाला कोटेश्वर राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2009 (14) एससीआर 1: (2009) 10 एससीसी 636; *कल्लू बनाम मध्य प्रदेश राज्य* 2006 (1) एससीआर 201: (2006) 10 एससीसी 313; *रमेश बाबूलाल दोशी बनाम गुजरात राज्य* 1996 (2) पूरक एससीआर 265: (1996) 9 एससीसी 225; *गणपत बनाम हरियाणा राज्य* 2010 (12) एससीआर 400: (2010) 12 एससीसी 59; *पंजाब राज्य बनाम कमैल सिंह* 2003 (2) पूरक एससीआर 593: (2003) 11 एससीसी 271; *जुगेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* 2012 (6) एससीआर 193: (2012) 6 एससीसी 297; *बसप्पा बनाम कर्नाटक राज्य* 2014 (3) एससीआर 391: (2014) 5 एसईसी 154–पर भरोसा किया गया।

2. अभियोजन पक्ष न केवल अपीलकर्ता की उपस्थिति स्थापित करने में सक्षम, रहा बल्कि गैरकानूनी सभा के सदस्य के रूप में उसकी सक्रिय भागीदारी भी स्थापित करने में सक्षम रहा था। हो सकता है कि उसने मृतक पर बम न फेंका हो, लेकिन इससे वह गैरकानूनी सभा का सदस्य बनना बंद नहीं करेगा जैसा कि आईपीसी की धारा 149 के दायरे में समझा जाता है और सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकालने के

लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए सभी आरोपी व्यक्तियों ने एक गैरकानूनी सभा का गठन किया था और मृतक पर हमला करना सामान्य उद्देश्य था, जिसने खुद को लगी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। विचारण न्यायाधीश का यह मानना था की यह एक खुली लड़ाई थी–उक्त निष्कर्ष स्पष्ट रूप से गलत था क्योंकि अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्थापित कर दिया था कि आरोपी व्यक्ति हमलावर थे। उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों के पुनर्मूल्यांकन और विश्लेषण पर पाया कि आरोपी व्यक्ति हमलावर थे। इसके अलावा, जैसा कि अभियोजन की पूरी कहानी से पता चलता है, आरोपी व्यक्ति घातक हथियारों से लैस होकर मृतक के घर गए और गंदी भाषा में गालियां दीं और विरोध करने पर उनमें से एक ने पूर्व-निर्धारित मन से मृतक के सीने पर बम फेंक दिया। इस प्रकार, यह ऐसा मामला है जहां अपीलकर्ता आईपीसी की धारा 149 की सहायता से धारा 302 के तहत दोषी ठहराए जाने के लायक था। गवाह, जैसा कि उच्च न्यायालय ने सही पाया, विश्वसनीय हैं और अपने कथन पर कायम हैं और अडिग बने हुए हैं। अभियोजन पक्ष के गवाहों, जो घटना के स्वाभाविक गवाह थे, के साक्ष्य में छोटी विसंगतियों और चूक पर जोर देना और अप्रासंगिक पहलुओं पर जोर देना और अंततः दोषमुक्ति को दर्ज करना, किसी भी कल्पना से इसे विचारण न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किया गया एक प्रशंसनीय या संभावित दृष्टिकोण नहीं माना जा सकता है और इसलिए, एक दोषी को बरी करने के फैसले को पलटना उच्च न्यायालय के लिए उचित था। [पैरा 26, 27, 29, 30] [813-डी-एफ; 814-ए-जी; 816-ई, एच; 817-ए-बी]

दलीप सिंह बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1953 एससी 364: 1954 एससीआर 145; *रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य* एआईआर 1952 एससी 54: 1952 एससीआर 377; *हरि ओबुला रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य* (1981) 3 एससीसी 675; *पंजाब राज्य बनाम जागीर सिंह* 1974 (1) एससीआर 328: (1974) 3 एससीसी 277; *अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य* 2010 (13) एससीआर 311: (2010) 10 एसईसी 259;

रामलगन सिंह बनाम बिहार राज्य (1973) 3 एससीसी 881; *मलखान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* (1975) 3 एससीसी 311; *विष्णु बनाम राजस्थान राज्य* (2009) 10 एससीसी 477; *बलराजे बनाम महाराष्ट्र राज्य* 2010 (6) एससीआर 764: (2010) 6 एससीसी 673; *जरनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य* 2009 (13) एससीआर 774: (2009) 9 एससीसी 719; *बालादीन बनाम यूपी राज्य* एआईआर 1956 एससी 181; *मसाल्टी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* एआईआर 1965 एससी 202: 1964 एससीआर 133; *भार्गवन बनाम केरल राज्य* 2003 (5) पूरक एससीआर 535: (2004) 12 एससीसी 414; *रामचन्द्रन बनाम केरल राज्य* 2011 (13) एससीआर 923: (2011) 9 एससीसी 257; *आंध्र प्रदेश राज्य बनाम ज्ञान चंद* 2001 (3) एससीआर 247: (2001) 6 एससीसी 71; *तखाजी हीराजी बनाम ठाकोर कुबेरसिंग चमनसिंह* (2001) 6 एससीसी 145; *दहारी बनाम यूपी राज्य 2012* (8) एससीआर 1219: (2012) 10 एसईसी 256–पर भरोसा किया गया।

निर्णय विधि संदर्भ

2009 (14) एससीआर 1	संदर्भित किया गया	पैरा 11
2006 (1) एससीआर 201	संदर्भित किया गया	पैरा 11
1996 (2) पूरक एससीआर 265	संदर्भित किया गया	पैरा 12
2010 (12) एससीआर 400	संदर्भित किया गया	पैरा 12
2003 (2) पूरक एससीआर 593	संदर्भित किया गया	पैरा 13
2012 (6) एससीआर 193	संदर्भित किया गया	पैरा 13
2014 (3) एससीआर 391	संदर्भित किया गया	पैरा 13
1954 एससीआर 1	भरोसा किया गया	पैरा 18
1952 एससीआर 377	भरोसा किया गया	पैरा 18

(1981) 3 एससीसी 675	भरोसा किया गया	पैरा 19
1974 (1) एससीआर 328	भरोसा किया गया	पैरा 20
2010 एससीआर 13	भरोसा किया गया	पैरा 21
(1973) 3 एससीसी 881	भरोसा किया गया	पैरा 21
(1975) 3 एससीसी 311	भरोसा किया गया	पैरा 21
(2009) 10 एससीसी 477	भरोसा किया गया	पैरा 21
2010 (6) एससीआर 764	भरोसा किया गया	पैरा 21
2009 (13) एससीआर 764	भरोसा किया गया	पैरा 21
एआईआर 1956 एससी 181	संदर्भित किया गया	पैरा 23
1964 एससीआर 133	संदर्भित किया गया	पैरा 23
2003 (5) पूरक एससीआर 535	संदर्भित किया गया	पैरा 24
2011 (13) एससीआर 923	संदर्भित किया गया	पैरा 25
2001 (3) एससीआर 247	संदर्भित किया गया	पैरा 28
(2006) 6 एससीसी 145	संदर्भित किया गया	पैरा 28
2012 (6) एससीआर 1219	संदर्भित किया गया	पैरा 28

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार; 2010 की आपराधिक अपील संख्या 1683

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के ग्वालियर पीठ के 1995 की आपराधिक अपील संख्या 214 में दिनांक 12.12.2005 के निर्णय और आदेश से।

वरिंदर कुमार शर्मा, विपिन कुमार, के. के. श्रीवास्तव (दीपक गोयल के लिए) अपीलार्थी के लिए।

सी. डी. सिंह प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा

1. वर्तमान अपील 1995 की आपराधिक अपील संख्या 214 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ की खंडपीठ द्वारा पारित दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश की बचाव योग्यता और कानूनी स्थिरता पर सवाल उठाती है जिसके तहत उच्च न्यायालय ने वर्तमान अपीलकर्ता सहित सभी आरोपी व्यक्तियों के संबंध में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 149 और आईपीसी 148 के साथ पठित धारा 302, 323, 324 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज की गई दोषमुक्ति के फैसले को खारिज कर दिया है और प्रत्येक आरोपी को आईपीसी की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के तहत सजा देने की कार्यवाही की और आजीवन कठोर कारावास के साथ-साथ अन्य अपराधों के लिए अलग-अलग सजाएं इस शर्त के साथ लगाई कि सभी सजाएं एक साथ होंगी। यह गौर करने वाली बात है कि अपीलकर्ता और एक मंगल सिंह पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3 और 4 के तहत भी मुकदमा चलाया गया था।

2. इस अपील के निपटारे के लिए जिन तथ्यों को उजागर किया जाना आवश्यक है, वे यह हैं कि 7.1.1984 को सुबह लगभग 9.00 बजे जब रत्ता, पीडब्लू-7, अपने घर पर था, आरोपी व्यक्ति, अर्थात् मंगल सिंह, बब्बू, जोधन, कन्छेदी, भिनुआ, रामस्वरूप और नत्थू और अन्य लोग लाठी, फरसा और हाथ से बने बम से लैस होकर वहां आए और रत्ता और उसके परिवार के सदस्यों के साथ गाली-गलौज करने लगे और कहा कि वे कुम्हारवालों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जैसा कि आरोप है, कनछेदी ने रुक्मणीबाई के बाएं हाथ पर फरसे से हमला किया, वर्तमान अपीलकर्ता जोधन ने हीरालाल, पीडब्लू-16 पर हस्तनिर्मित बम फेंककर उसके दाहिने पैर में चोट पहुंचाई और आरोपी मंगल सिंह ने सिरिया उर्फ श्रीराम की छाती पर हस्तनिर्मित बम फेंका जिससे

उसे गंभीर चोटें आईं। अन्य आरोपियों ने घटना में लाठियां चलायीं। जैसे अभियोजन की कहानी आगे बढ़ती है, रत्ता ने 7.1.1984 को लगभग 12.15 बजे एक एफआईआर, प्रदर्श पी/24 दर्ज की और उस समय तक सिरिया उर्फ श्रीराम की चोटों के कारण पहले ही मौत हो चुकी थी। घायल व्यक्तियों की चिकित्सीय जांच की गई और जांच एजेंसी के अनुरोध पर पोस्टमॉर्टम किया गया। जांच एजेंसी ने जांच के दौरान घटनास्थल का नक्शा तैयार किया, घटना स्थल से खून से सनी मिट्टी एकत्र की और आगे, जैसा कि स्पष्ट है, आरोपी व्यक्तियों के बताए अनुसार हथियार, अर्थात् लाठी, फरसा और हस्तनिर्मित बम जब्त किए और इसके बाद, जब्त किए गए सामानों को विश्लेषण के लिए रासायनिक परीक्षक के पास भेज दिया। जांच अधिकारी ने गवाहों के बयान दर्ज किए और अंततः आरोप पत्र मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, विदिशा के न्यायालय में पेश किया, जिसने बदले में, मामले को सत्र न्यायालय, विदिशा को सौंप दिया।

3. विद्वान विचारण न्यायाधीश ने सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 323, 324 के साथ पठित धारा 149 और 148 के तहत आरोप तय किए और आरोपी कनछेदी के खिलाफ आईपीसी की धारा 324 के तहत और जोधन और मंगल सिंह के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अतिरिक्त आरोप तय किए।

4. आरोपी व्यक्तियों ने खुद को निर्दोष बताया और गलत फंसाने की दलील दी। आरोपी व्यक्तियों का यह भी मामला था कि मुखबिर और अन्य लोगों ने बब्बू खंगार को एक कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ मारपीट की और बब्बू को लगी चोटों के कारण बाद में उसकी मृत्यु हो गई।

5. आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 16 गवाहों का परीक्षण किया और कई दस्तावेजों को प्रदर्श के रूप में चिह्नित किया। मुकदमे के दौरान मिश्री, पीडब्लू-1, हरनाम सिंह, पीडब्लू-3, तुलसा

बाई, पीडब्लू-4 और हजरत सिंह, पीडब्लू-5 ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया और तदनुसार अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने रिकॉर्ड पर साक्ष्य का अवलोकन करते हुए कुछ विसंगतियों को दर्ज किया, अभियोजन पक्ष के पक्ष में गवाही देने वाले गवाहों की गवाही पर संदेह व्यक्त किया, न्यायालय में लंबित मामलों को संदर्भित किया, पक्षों के बीच खुली लड़ाई, आरोपी व्यक्तियों को लगी चोटों के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा संतोषजनक स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति, रिकॉर्ड पर स्वतंत्र साक्ष्य की अनुपस्थिति का उल्लेख किया और तदनुसार अभियोजन की कहानी पर अविश्वास किया और सभी आरोपी व्यक्तियों को बरी कर दिया।

6. इस समय, यह ध्यान देने योग्य है कि जिस बाबूलाल को एफआईआर में आरोपी के रूप में आरोपित किया गया था, आरोप पत्र दाखिल होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई और इसलिए, छह आरोपी व्यक्तियों को मुकदमे का सामना करना पड़ा।

7. बरी किए जाने के फैसले से असंतुष्ट होकर, राज्य ने छह आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक अपील को प्राथमिकता दी। अपील के लंबित रहने के दौरान मंगल सिंह की मृत्यु हो गई और उसके खिलाफ अपील निरस्त कर दी गई। उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों पुनरावलोकन किया और राय दी कि विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत था और इसे स्वीकार्य नहीं माना जा सकता था और तदनुसार, इसे उलट दिया और दोषसिद्धि दर्ज की और सजा सुनाई जैसा की यहाँ पहले बताया गया है। इसलिए, यह वर्तमान अपील। वर्तमान अपीलकर्ता को छोड़कर, अन्य आरोपी व्यक्तियों ने कोई अपील नहीं की है।

8. हमने अपीलकर्ता के विद्वान वकील, श्री वरिंदर कुमार शर्मा और प्रतिवादी के विद्वान वकील, श्री सी.डी. सिंह को सुना है।

9. अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय को बरी करने के आदेश को रद्द करते समय अपीलीय शक्ति का उपयोग बहुत जिम्मेदारी और सावधानी से करना चाहिए और यह पर्याप्त बाध्यकारी कारणों से होना चाहिए और अपीलीय न्यायालय को बरी करने के फैसले को तब तक पलटना नहीं चाहिए जब तक कि उसे यह न लगे कि यह पूरी तरह से विकृत और पूरी तरह से अस्थिर है। उन्होंने कहा कि मौजूदा मामले में विद्वान विचारण न्यायाधीश ने रिकॉर्ड पर लाए गए सबूतों का उचित तरीके से विश्लेषण किया था, विसंगतियों और विरोधाभासों को दर्ज किया था और इसलिए, उनके द्वारा व्यक्त किया गया विचार विश्वसनीय होने के कारण, उच्च न्यायालय की ओर से इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार या औचित्य नहीं था। विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि जिन गवाहों पर उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा किया गया है, वे मुखबिर के परिवार के सदस्य होने के नाते हितबद्ध गवाह हैं और जब अन्य सभी स्वतंत्र गवाहों ने अभियोजन पक्ष के पक्ष में गवाही नहीं दी है, तो विचारण न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण स्वीकार्यता के योग्य है। श्री शर्मा द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष यह बताने में विफल रहा है कि घटनास्थल पर मौजूद अन्य चश्मदीद गवाहों से पूछताछ क्यों नहीं की गई और उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह के स्पष्टीकरण का उचित अवलोकन नहीं किया गया, उलटफेर का निर्णय अरक्षणीय है। श्रीमान शर्मा का यह भी तर्क है कि जब अपीलकर्ता ने मृतक को कोई चोट नहीं पहुंचाई थी, तो उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए था, क्योंकि वह केवल अपने प्रकट कृत्य के लिए उत्तरदायी होगा, दूसरों के लिए नहीं।

10. राज्य के विद्वान वकील श्री सी.डी. सिंह का कहना है कि विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के उचित अवलोकन पर आधारित नहीं हैं और वास्तव में, वे विकृत और पूरी तरह से अपुष्ट हैं और इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा फैसले में हस्तक्षेप करना उचित है। उनके द्वारा आग्रह

किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किए गए बरी करने के विचार को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। श्री सिंह का मानना है कि विद्वान ट्रायल न्यायाधीश द्वारा जो विसंगतियां और विरोधाभास महसूस किए गए हैं, वे बिल्कुल मामूली हैं और वास्तव में वे अभियोजन पक्ष के संस्करण पर हल्का सा प्रभाव भी नहीं डालते हैं। उनका आगे यह कहना है कि जिन प्रमुख गवाहों को हितबद्ध गवाह के रूप में नामित किया गया है, वे करीबी परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने घटना देखी थी और इसके अलावा उन्हें घटना में चोटें भी आई थीं, और इसलिए, उनकी गवाही पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि जब अभियोजन पक्ष रिकॉर्ड पर लाए गए सबूतों के आधार पर उचित संदेह से परे मामले को स्थापित करने में सक्षम है, तो उसके संस्करण को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि अन्य स्वतंत्र गवाहों की जांच नहीं की गई थी, क्योंकि यहां तक कि कुछ परिस्थितियों में किसी भौतिक गवाह की जांच न करने के लिए भी अभियोजन मुक्त है और मौजूदा मामले में आरोपी व्यक्तियों द्वारा यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है कि गवाह एक ऐसा भौतिक गवाह था जिसके साक्ष्य के बिना अभियोजन पक्ष के संस्करण का ढह जाना या लड़खड़ा जाना तय था। अंत में, श्री सिंह द्वारा यह चित्रित किया गया है कि जब आरोपी व्यक्तियों ने एक गैरकानूनी सभा का गठन किया, तो धारा 149 पूरी तरह से आकर्षित हो जाती है और उस परिस्थिति में अपीलकर्ता को यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वह आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि उसने मृतक पर हमला नहीं किया था।

11. बार में उठाए गए निवेदनों का अवलोकन करने के लिए, हम दोषमुक्ति के फैसले के खिलाफ अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय अपीलीय अदालत की शक्ति से निपटना प्रासंगिक समझते हैं। गामिनी बाला कोटेश्वर राव बनाम ए.पी. राज्य[1] में इस न्यायालय ने माना है कि यह कानून में अच्छी तरह से स्थापित है कि

विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए सबूतों और निष्कर्षों का पुनर्मूल्यांकन करना उच्च न्यायालय के लिए खुला है, लेकिन केवल उस मामले में जब विचारण न्यायालय के निर्णय को विकृत बताया गया है। कानून में समझे जाने वाले शब्दों में 'विकृत' शब्द को 'साक्ष्य के वजन के विरुद्ध' के रूप में परिभाषित किया गया है। कल्लू बनाम एमपी राज्य[2] के मामले में, यह माना गया है कि यदि विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक विश्वसनीय दृष्टिकोण है, तो उच्च न्यायालय द्वारा इसे उलट देना केवल इसलिए उचित नहीं होगा क्योंकि एक अलग दृष्टिकोण संभव है। इसे और विस्तार से बताते हुए यह फैसला सुनाया गया है कि बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर बताते हुए यह फैसला सुनाया गया है कि बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर फैसला करते समय, अपीलीय अदालत की शक्ति दोषसिद्धि के खिलाफ अपील की सुनवाई करते समय प्रयोग की गई शक्ति से कम नहीं है। दोनों प्रकार की अपीलों में संपूर्ण साक्ष्य कीसमीक्षा करने की शक्ति मौजूद है। हालाँकि, एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि बरी करने के आदेश में अपीलीय अदालत द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, जहां विचारण न्यायालय का निर्णय साक्ष्य पर आधारित है और लिया गया दृष्टिकोण उचित और विश्वसनीय है। यह ट्रायल कोर्ट के फैसले को केवल इसलिए पलट नहीं देगा क्योंकि एक अलग दृष्टिकोण संभव है। अपीलीय अदालत यह भी ध्यान में रखेगी कि अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषता का अनुमान है और अभियुक्त किसी भी संदेह का लाभ पाने का हकदार है।

12. रमेश बाबूलाल दोशी बनाम गुजरात राज्य[3] में, इस न्यायालय ने यह विचार किया है कि बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर विचार करते समय, अपीलीय अदालत को पहले इस प्रश्न का उत्तर मांगना आवश्यक है कि क्या विचारण न्यायालय के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से गलत हैं, प्रमाणित रूप से अरक्षणीय या साफ तौर पर त्रुटिपूर्ण है और यदि न्यायालय उपरोक्त प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में देती है, तो दोषमुक्ति में

बाधा नहीं डाली जा सकती। गणपत बनाम हरियाणा राज्य[4] में, पहले के प्राधिकारों का हवाला देने के बाद कुछ सिद्धांतों को हटा दिया गया है। वे इस प्रकार पढे जाते हैं:-

"15. अपीलीय अदालत को अपीलों से निपटते समय, विशेष रूप से बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ, निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा:

(i) अपीलीय अदालत की ओर से उन सबूतों की समीक्षा करने और अपने निष्कर्ष पर पहुंचने की कोई सीमा नहीं है, जिन पर बरी करने का आदेश आधारित है।

(ii) अपीलीय अदालत तथ्यों और कानून दोनों के संबंध में विचारण न्यायालय के निष्कर्ष की समीक्षा भी कर सकती है।

(iii) राज्य द्वारा की गई अपील से निपटते समय, अपीलीय अदालत का यह कर्तव्य है कि वह पूरे साक्ष्य को रिकॉर्ड पर रखे और ठोस और पर्याप्त कारण देकर बरी करने के फैसले को रद्द कर सकती है।

(iv) बरी करने के आदेश में तभी हस्तक्षेप किया जाना चाहिए जब ऐसा करने के लिए 'अकाट्य और पर्याप्त कारण' हों। यदि आदेश 'स्पष्ट रूप से अनुचित' है, तो यह हस्तक्षेप का एक अनिवार्य कारण है।

(v) जब विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों को नजरअंदाज कर दिया है या भौतिक साक्ष्यों को गलत तरीके से पढ़ा है या मृत्युपूर्व घोषणा/प्राक्षेपिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट आदि जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को नजरअंदाज कर दिया है, तो अपीलीय अदालत रखी गई सामग्रियों के आधार पर विचारण न्यायालय के फैसले को उलटने में सक्षम है।"

13. पंजाब राज्य बनाम करनैल सिंह[5] में, न्यायालय ने कहा कि न्यायालय का सर्वोपरि विचार यह सुनिश्चित करना है कि न्याय की निष्फलता को रोका जाए। दोषियों को बरी करने से होने वाली न्याय की हानि किसी निर्दोष को दोषी ठहराए जाने से कम नहीं है। ऐसे मामले में जहां स्वीकार्य सबूतों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, अपीलीय न्यायालय पर यह कर्तव्य बनता है कि वह सबूतों का फिर से पुनरावलोकन

करे, भले ही आरोपी को बरी कर दिया गया हो, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपियों में से किसी ने कोई अपराध किया है या नहीं। जुगेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य[6] और बसप्पा बनाम कर्नाटक राज्य[7] में उपरोक्त सिद्धांतों को दोहराया गया है।

14. कानूनी सिद्धांतों के पूर्वोक्त प्रतिपादन को ध्यान में रखते हुए हमें यह जांचना होगा कि क्या विद्वान परीक्षण न्यायाधीश द्वारा साक्ष्य का अवलोकन इतना अस्वीकार्य था कि उचित तरीके से नहीं किया गया था और इसलिए, यह उच्च न्यायालय का दायित्व था कि वह साक्ष्य का पुनरावलोकन करे और दोषसिद्धि दर्ज करें। इससे पहले कि हम यहां ऊपर बताए गए मापदंडों के भीतर बरी करने के फैसले में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के आधार पर आगे बढ़ें, हम मृतक सिरिया उर्फ श्रीराम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का उल्लेख करना उचित समझते हैं। डॉ. अरुण कुमार श्रीवास्तव, पीडब्लू-13, ने शव का पोस्टमार्टम किया है और अपनी रिपोर्ट, प्रदर्श पी-32, में उन्होंने निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किए हैं:-

> "जले हुए क्षेत्र का पूर्ण मोटाई वाला काला पड़ा हुआ सतत पैच और छाती के सामने की त्वचा का अधिकांश भाग त्वचा के भुने हुए पैच के रूप में है। छाती के ऊपर जला हुआ क्षेत्र 1 सेमी मोटाई की त्वचा के लाल क्षेत्र से घिरा हुआ है। यह जला हुआ क्षेत्र ठोड़ी के सबमेंटल क्षेत्र से लेकर पार्श्व में दोनों सबमेंडीबूलर क्षेत्र तक फैला हुआ है, नीचे की ओर जाने पर जला हुआ क्षेत्र गर्दन के सामने और किनारों पर सुप्रास्टर्नल नोच के ऊपर बड़ा हो जाता है। फिर स्टर्नम की पार्श्व सीमा से परे 29 सेमी माप वाला जला हुआ क्षेत्र है। अधिकतम ऊर्ध्वाधर लंबाई और सबसे चौड़ा क्षेत्र 14 सेमी का है। इस जले हुए स्थान पर तीन कटे हुए घाव मौजूद हैं।

1. कटा हुआ घाव - स्टर्नम की पार्श्व सीमा के करीब 3 सेमी x 1 सेमी x 1 सेमी गहराई के करीब बाएं चौथे इंटरकोस्टल स्पेस पर तिरछा बना हुआ।

2. स्टर्नम की पार्श्व सीमा के निकट स्टर्नम पर 1 सेमी x ½ सेमी x त्वचा की गहराई तक कटा हुआ घाव।

3. कटा हुए घाव के मध्य से स्टर्नम के ऊपर त्वचा की गहराई तक कटा हुआ, घाव नं. 2, ½ सेमी x ¼ सेमी।

इन घावों में कोई बाह्य तत्व नहीं मिला।

बाएं हाथ पर बायीं तर्जनी अंगुली के संबंध में मेटाकार्पल हड्डी के ऊपर पृष्ठीय और दूर स्थित जलने के निशान का काला पड़ा हुआ रोस्टर पैच 3 सेमी x 1.5 सेमी।"

15. शव परीक्षण शल्य चिकित्सक के साक्ष्य के अनुसार, मृतक की मृत्यु व्यापक रक्तस्राव, सदमे और फेफड़ों के संपीड़न के कारण हुई और चोटें विस्फोटक पदार्थ के कारण लगी थी। पीडब्लू-13 की गवाही और मृतक को लगी चोटों के अवलोकन पर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मौत प्रकृति में हत्या थी और विस्फोटक पदार्थ के कारण हुई थी। रिकार्ड से पता चलता है कि घटना में अन्य गवाहों को भी चोटें आयीं थीं। जैसा कि देखा गया है, रत्ता, पीडब्लू-7, रुक्मणीबाई, पीडब्लू-14, रामबाई, पीडब्लू-15 और हीरालाल, पीडब्लू-16, जो मृतक से संबंधित हैं, चश्मदीद गवाह हैं और उन्होंने अभियोजन संस्करण का समर्थन किया है। सभी गवाहों को चोटें आई हैं। उपचार कर रहे चिकित्सक के अनुसार, हीरालाल, पीडब्लू-16 को दाहिने पैर के पृष्ठ भाग पर विस्फोट से चोट लगी थी और काला पड़ गया था। उन्हें दाहिने पैर के एक्स-रे की सलाह दी गई थी। रुक्मणीबाई, पीडब्लू-14, के बाएं हाथ पर (पीछे) एक अग्रवर्ती कटा हुआ घाव हो गया था। 5 वें मेटाकार्पल के आधार से दूसरे मेटाकार्पल के ऊपर तक

30½ x ¼ x त्वचा में गहराई तक मांसपेशियां आंशिक रूप से कटी हुई, बाईं कलाई के पीछे घर्षण ¼" x ¼", और बाएं पैर के निचले अग्रभाग में घर्षण 1/3" x ¼"। चोट रिपोर्ट के अनुसार, चोट नं. 1 नुकीली वस्तु से लगी थी और अन्य चोटें कठोर और कुंद वस्तु से लगी थीं। रत्ता, पीडब्लू-7 को बाएं पैर पर टिबियल लुबरोसिटी पर 1 1/2" x 1" घर्षण बना हुआ था। सभी चोटें कठोर और कुंद वस्तु से लगी थीं। अन्य गवाहों को भी इसी तरह चोटें आई थीं। चश्मदीद गवाहों के शरीर पर चोटें पीडब्लू-12 द्वारा सिद्ध की गई हैं और एमएलसी रिपोर्ट द्वारा समर्थित हैं।

16. मृतक और गवाहों को लगी चोटों को ध्यान में रखते हुए, यह जांच की जानी चाहिए कि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा क्या गवाही दी गई है, जिसे उच्च न्यायालय ने विद्वान परीक्षण न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किये गये विचार से असहमत होते हुए विश्वसनीयता प्रदान की है। जैसा कि पहले कहा गया है, चश्मदीद गवाह रत्ता, पीडब्लू-7, रुक्मणीबाई, पीडब्लू-14, रामबाई, पीडब्लू-15 और हीरालाल, पीडब्लू-16 हैं। रत्ता, पीडब्लू-7 के साक्ष्य के अनुसार, आरोपी व्यक्ति, अर्थात्, जोधन, रामस्वरूप, भेरोसिंह उर्फ भिनुआ, बब्बू उर्फ बाबूलाल, नत्थू, मंगल सिंह और कंछेदी उसके घर के पास आए और गंदी भाषा में गाली दी। मृतक सिरिया ने आकर मंगल सिंह द्वारा की जा रही गालियों का विरोध किया, जिसने तुरंत हाथ से बने बम सिरिया की छाती पर फेंक दिया, जिससे सिरिया घायल हो गया। जोधन ने हीरालाल, पीडब्लू-16 पर एक हाथ से बना हुआ बम फेंका और अन्य आरोपियों ने घायल व्यक्तियों पर हमला किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, ग्रामीण मौके पर आए और मंगल सिंह और बाबूलाल को पकड़ लिया और सिरिया के घर में बंद कर दिया। रत्ता ने एफआईआर, प्रदर्श पी-24, दर्ज की और घायल सिरिया, हीरालाल और रुक्मणीबाई और अन्य को अस्पताल लेकर आया। सिरिया उर्फ श्रीराम को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और जैसा कि पहले कहा गया है, अन्य घायल व्यक्तियों ने उपचार लिया।

17. रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य के अनुसार, घटना मृतक और गवाहों के घर के पास हुई थी। इन गवाहों के खिलाफ जो आलोचना की गई है, उसका प्रभाव यह है कि वे हितबद्ध गवाह हैं और इसलिए, उनका बयान बिना योग्यता के स्वीकार्यता के लायक नहीं है, क्योंकि वे गवाह हैं जो घटनास्थल पर थे और उन्हें चोटें आई थीं। वे करीबी रिश्तेदार हैं और तीखे प्रतिपरिक्षण के बावजूद वे मजबूती से खड़े हैं। इस प्रस्ताव पर कोई संदेह नहीं हो सकता है कि जब गवाह संबंधित और हितबद्ध हैं, तो उनकी गवाही की बारीकी से जांच की जानी चाहिए, लेकिन जैसा कि हमने पाया है, जिरह में उनके संस्करण को अविश्वसनीय मानने के लिए कुछ भी नहीं मिला है। उनके सबूतों की जांच करने पर, यह निश्चितता के साथ कहा जा सकता है कि उन्होंने सभी भौतिक विवरणों में एक-दूसरे के संस्करण का समर्थन किया है। कुछ छोटे विरोधाभास और चूक हैं जिन पर विद्वान विचारण न्यायाधीश ने जोर दिया है। उच्च न्यायालय ने उक्त विसंगतियों और छोटे-मोटे विरोधाभासों को स्वाभाविक माना है। इसके अलावा, उनके सबूतों को मेडिकल साक्ष्य और एफआईआर में लगाए गए शुरुआती आरोपों से भी समर्थन मिलता है। उच्च न्यायालय ने राय दी है कि उनके संस्करण में कोई असंगतता नहीं है और उक्त साक्ष्यों के अवलोकन पर, हमने पाया कि बिल्कुल भी कोई असंगतता नहीं है जो कानून के न्यायालय को उनके संस्करण को खारिज करने के लिए मजबूर करेगी। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने, जैसा कि अप्राप्य है, ऐसी चूकों और विरोधाभासों पर अत्यधिक जोर दिया है, जो उच्च न्यायालय के अनुसार बिल्कुल महत्वहीन और तुच्छ हैं, जिससे हम सहमत हैं। यह भी माना जाता है कि विद्वान विचारण न्यायाधीश ने इस तथ्य पर उल्लेखनीय जोर दिया है कि मुखबिर की पार्टी द्वारा उनके पक्ष में मतदान न करने के कारण आरोपी व्यक्ति और मुखबिर शत्रुतापूर्ण स्थिति में थे। हमारी सुविचारित राय में, वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन करने वाले चश्मदीद गवाहों पर भरोसा न करने का यह आधार नहीं हो सकता है।

18. अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री शर्मा द्वारा यह जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि जब गवाह इच्छुक गवाह हैं और अन्य स्वतंत्र गवाह मुकर गए हैं, तो उच्च न्यायालय को ऐसे गवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था और विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा बरी किए जाने के फैसले को नहीं पलटना चाहिए था। सबसे पहले, हम संबंधित गवाहों की विश्वसनीयता से निपटेंगे। दलीप सिंह बनाम पंजाब राज्य[8] में, यह इस प्रकार देखा गया है: -

> "हम उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों से सहमत होने में असमर्थ हैं कि दो चश्मदीदों की गवाही की पुष्टि की आवश्यकता है। यदि इस तरह के अवलोकन का आधार इस तथ्य पर आधारित है कि गवाह महिलाएं हैं और सात पुरुषों का भाग्य उनकी गवाही पर निर्भर है, तो हम ऐसे किसी नियम के बारे में नहीं जानते हैं। यदि यह इस कारण पर आधारित है कि उनका मृतक से गहरा संबंध है तो हम सहमत होने में असमर्थ हैं। यह कई आपराधिक मामलों में आम भ्रांति है और जिसे इस न्यायालय की अन्य पीठ ने रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य[9] में दूर करने का प्रयास किया था।"

उक्त मामले में आगे यह भी देखा गया है:-

> "एक गवाह को आम तौर पर तब तक स्वतंत्र माना जाता है जब तक कि वह ऐसे स्रोतों से नहीं आता है जो दागी होने की संभावना है और आमतौर पर इसका मतलब यह है कि जब तक कि गवाह के पास उसे झूठा फंसाने की इच्छा रखने के लिए अभियुक्त के प्रति शत्रुता जैसा कोई कारण न हो। आम तौर पर कोई करीबी [रिश्तेदार] असली अपराधी को उजागर करने और किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फंसाने के लिए आखिरी व्यक्ति होता है। यह सच है, जब भावनाएँ चरम पर

होती हैं और शत्रुता का व्यक्तिगत कारण होता है, तो दोषी के साथ-साथ एक निर्दोष व्यक्ति को भी घसीटने की प्रवृत्ति होती है जिसके प्रति गवाह के मन में द्वेष हो, लेकिन ऐसी आलोचना के लिए नींव रखी जानी चाहिए और रिश्ते की बुनियाद से कोसों दूर का तथ्य अक्सर सच्चाई की पक्की गारंटी होता है।"

19. हरि ओबुला रेड्डी बनाम ए.पी.[10] राज्य में, न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि हितबद्ध गवाहों के साक्ष्य को अविश्वसनीय साक्ष्य नहीं कहा जा सकता है। एकमात्र गवाही को बदनाम करने या खारिज करने के लिए पक्षपात अपने आप में एक वैध आधार नहीं है। हम उक्त प्राधिकार से एक अंश को उपयोगी ढंग से पुन: प्रस्तुत कर सकते हैं: -

"एक अटल नियम है कि हितबद्ध साक्ष्य कभी भी दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकते जब तक कि स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा भौतिक विवरण में भौतिक सीमा तक पुष्टि न की जाए। बस इतना आवश्यक है कि इच्छुक गवाहों के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच की जाए और सावधानी के साथ स्वीकार किया जाए। यदि ऐसी जांच पर, इच्छुक गवाही आंतरिक रूप से विश्वसनीय या स्वाभाविक रूप से संभावित पाई जाती है, तो यह, विशेष मामले की परिस्थितियों में, उस पर दोषसिद्धि का आधार बनाने के लिए, अपने आप में पर्याप्त हो सकती है।

20. कई निर्णयों में जो सिद्धांत बताए गए हैं उनका प्रभाव यह है कि किसी इच्छुक गवाह के साक्ष्य पर भरोसा किया जा सकता है यदि वह भरोसेमंद और विश्वसनीय पाया जाता है। कहने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई गवाही सावधानीपूर्वक जांच के बाद अविश्वसनीय और असंभव या संदिग्ध पाई जाती है तो उसे

खारिज कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, जब किसी गवाह का कोई मकसद होता है या वह गलत आशय लगाता है, तो अदालत को उसकी गवाही पर भरोसा करने से पहले भौतिक विवरणों के संबंध में पुष्टि मांगनी चाहिए। मौजूदा मामले में, जिन गवाहों ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ गवाही दी है, वे करीबी रिश्तेदार हैं और घटना में उन्हें चोटें आई थीं। घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है, उनका बयान सुसंगत है और प्रतिपरिक्षण में उनकी गवाही को हिला देने वाली कोई बात सामने नहीं आई है। कुछ छोटी-मोटी विसंगतियां हैं, लेकिन वास्तव में वे अपने साक्ष्यों पर कोई असर नहीं डालती हैं, जिससे उन्हें असंभव या अविश्वसनीय माना जा सके। इस संदर्भ में, पंजाब राज्य बनाम जागीर सिंह[11] मामले में न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को उद्धृत करना आवश्यक है:-

> "एक आपराधिक मुकदमा एक परी कथा की तरह नहीं है जिसमें कोई अपनी कल्पना और विचारों को उड़ान देने के लिए स्वतंत्र है। यह स्वयं इस प्रश्न से संबंधित है कि क्या मुकदमे में दोषी ठहराया गया अभियुक्त उस अपराध का दोषी है जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है। अपराध वास्तविक जीवन की एक घटना है और विभिन्न मानवीय भावनाओं के परस्पर क्रिया का उत्पाद है। अदालत को सबूतों को संभावनाओं, उसके आंतरिक मूल्य और गवाहों की दुश्मनी के पैमाने पर आंकना होगा। अंतिम विश्लेषण में प्रत्येक मामले को अपने तथ्यों पर निर्भर रहना होगा। यद्यपि हर उचित संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए, लेकिन अदालतों को उन सबूतों को अस्वीकार नहीं करना चाहिए जो काल्पनिक या अनुमान की प्रकृति के आधार पर भरोसेमंद हैं।"

21. कानून की उपरोक्त व्याख्या की पृष्ठभूमि पर परीक्षण करते हुए, हम अपीलकर्ता के विद्वान वकील की इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि उच्च

न्यायालय उक्त अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य पर भरोसा करके गलती में पड़ गया है। यह दलील कि जब अन्य गवाह मुकर गए हैं, तो इन गवाहों के संस्करण पर भी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, इसे स्वीकार करना उचित नहीं है, क्योंकि साक्ष्य का कोई नियम नहीं है कि इच्छुक गवाहों की गवाही को केवल इसलिए खारिज कर दिया जाए क्योंकि साक्ष्य का कोई नियम नहीं है कि इच्छुक गवाहों की गवाही केवल इसलिए खारिज कर दी जाएगी क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा उद्धृत अन्य स्वतंत्र गवाह मुकर गए हैं। इसके अतिरिक्त, हम लाभ के साथ नोट कर सकते हैं कि इन गवाहों को चोटें लगी थीं और उनके साक्ष्य हमें ठोस और विश्वसनीय लगे। एक घायल गवाह की गवाही अन्य गवाहों की तुलना में ऊंचे स्थान पर होती है। अब्दुल सईद बनाम एम.पी. राज्य [12] के मामले में, यह देखा गया है कि एक गवाह, जो घटना के दौरान खुद घायल हो गया था, के साक्ष्य को महत्व देने के सवाल पर इस न्यायालय द्वारा बड़े पैमाने पर चर्चा की गई है। जहां घटना का गवाह खुद घटना में घायल हो गया हो, ऐसे गवाह की गवाही आम तौर पर बहुत विश्वसनीय मानी जाती है, क्योंकि वह एक गवाह है जो अपराध स्थल पर अपनी उपस्थिति की अंतर्निहित गारंटी के साथ आता है और किसी को झूठा फंसाने के लिए अपने वास्तविक हमलावरों को छोड़ने की संभावना नहीं है। यह भी दोहराया गया है कि किसी घायल गवाह पर अविश्वास करने के लिए ठोस सबूत की आवश्यकता होती है। जैसे कि राय, रामलगन सिंह बनाम बिहार राज्य [13], मलखान सिंह बनाम यूपी राज्य [14], विष्णु बनाम राजस्थान राज्य [15] और बलराजे बनाम महाराष्ट्र राज्य [16] और जरनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य [17] पर भरोसा करते हुए व्यक्त की गई थी।

22. कानूनी सिद्धांतों के उपरोक्त सारांश से, यह संदेह से परे है कि घायल गवाह की गवाही का अपना महत्व है और उस पर भरोसा करना होगा जब तक कि प्रमुख विरोधाभासों और विसंगतियाँ के आधार पर उसके साक्ष्य को अस्वीकार करने के लिए मजबूत आधार न हों। जैसा कि कहा गया है, घायल गवाह को कानून में विशेष

दर्जा दिया गया है और उसे लगी चोट घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति की अंतर्निहित गारंटी है। इस प्रकार देखने पर, हमें वास्तव में अपीलकर्ता के विद्वान वकील की दलील में कोई तथ्य नहीं मिलता है कि घायल गवाहों के साक्ष्य को विद्वान परीक्षण न्यायाधीश द्वारा अविश्वसनीय मानकर खारिज कर दिया गया है।

23. श्री शर्मा द्वारा उजागर किए गए तर्कों में से एक यह है कि धारा 149 आईपीसी की सहायता से वर्तमान अपीलकर्ता को दोषी ठहराने का उच्च न्यायालय की ओर से कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के अनुसार, उसने मृतक को कोई चोट पहुंचाने के लिए कोई प्रत्यक्ष कार्य नहीं किया था। उपरोक्त प्रस्तुतीकरण इस प्रस्ताव को मानता है कि भले ही गैरकानूनी जमावड़े का तथ्य अभियोजन पक्ष द्वारा साबित कर दिया गया हो, फिर भी न्यायालय को प्रत्येक अभियुक्त के व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कृत्यों पर ध्यान देना आवश्यक है। बालादीन बनाम यूपी राज्य[18] में, यह माना गया था कि किसी सभा में उपस्थिति मात्र से ऐसे व्यक्ति को गैरकानूनी सभा का सदस्य नहीं बनाया जा सकता है, जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि उसने कुछ किया है या ऐसा कुछ करने से चूक गया है जो उसे एक गैरकानूनी सभा का सदस्य बना देगा। उक्त मामले में तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दर्ज की गई टिप्पणियों को मसाल्टी बनाम यूपी राज्य[19] में चार-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा स्पष्ट किया गया था, जिसमें बड़ी पीठ ने बालादीन (ऊपर) में की गई टिप्पणियों को अलग किया और राय दी कि उक्त टिप्पणियों को मामले के विशेष तथ्यों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। मसाल्टी (ऊपर) में जो आदेश दिया गया है उसका निम्नलिखित प्रभाव है:

> "...यह कहना सही नहीं होगा कि किसी व्यक्ति को गैरकानूनी सभा का सदस्य ठहराए जाने से पहले, यह दिखाया जाना चाहिए कि उसने सभा के सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में कुछ अवैध प्रत्यक्ष कार्य किया था या कुछ अवैध चूक का दोषी था। वास्तव में, धारा 149 यह

स्पष्ट करती है कि यदि किसी गैरकानूनी सभा के किसी भी सदस्य द्वारा उस सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में कोई अपराध किया जाता है, या उस सभा के सदस्यों को पता था कि उस सभा के उद्देश्य के अभियोजन में अपराध किए जाने की संभावना है, प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध को करने के समय उसी सभा का सदस्य है, उस अपराध का दोषी है; और यह सशक्त रूप से इस सिद्धांत को सामने लाता है कि धारा 149 द्वारा निर्धारित सजा एक अर्थ में प्रतिगामी है और हमेशा इस आधार पर आगे नहीं बढ़ती है कि अपराध वास्तव में गैरकानूनी सभा के प्रत्येक सदस्य द्वारा किया गया है।"

24. भार्गवन बनाम केरल राज्य[20] में, यह कहा गया है: -

"... इसे कानून के सामान्य प्रस्ताव के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष कृत्य साबित नहीं होता है, जिस पर गैरकानूनी सभा का सदस्य होने का आरोप है, यह नहीं कहा जा सकता है कि वह किसी सभा का सदस्य है। केवल एक चीज की आवश्यकता है कि उसे यह समझना चाहिए कि सभा गैरकानूनी थी और आईपीसी की धारा 141 के दायरे में आने वाले किसी भी कार्य को करने की संभावना थी।"

25. इस संदर्भ में, हम रामचन्द्रन बनाम केरल राज्य[21] के एक अंश को उपयोगी ढंग से पुन: प्रस्तुत कर सकते हैं:

"इस प्रकार, यह न्यायालय निर्णयों की श्रृंखला में बहुत सतर्क रहा है कि जहां बड़ी संख्या में व्यक्तियों के खिलाफ सामान्य आरोप लगाए गए हैं, अदालत स्पष्ट रूप से सबूतों की जांच करेगी और यदि रिकॉर्ड

पर उपलब्ध साक्ष्य अस्पष्ट है तो बड़ी संख्या में व्यक्तियों को दोषी ठहराने में संकोच करेगी। अदालत के लिए यह जांच करना अनिवार्य है कि यदि किया गया अपराध सामान्य उद्देश्य के सीधे अभियोजन में नहीं है, तो भी यह आईपीसी की धारा 149 के दूसरे भाग के अंतर्गत आ सकता है, यदि अपराध ऐसा था जिसके सदस्यों को पता था कि अपराध होने की संभावना है। आगे यह निष्कर्ष निकालना होगा कि व्यक्तियों की संख्या क्या थी; उनमें से कितने केवल निष्क्रिय गवाह थे; उनके अस्त्र-शस्त्र क्या थे। चोटों की संख्या और प्रकृति पर भी विचार करना प्रासंगिक है। 'सामान्य उद्देश्य' घटना के समय भी विकसित किया जा सकता है।"

26. कानून की उपरोक्त राय के आधार पर, श्री शर्मा द्वारा दायर की गई दलील किसी भी विचार के लायक नहीं है क्योंकि अभियोजन न केवल अपीलकर्ता की उपस्थिति स्थापित करने में सक्षम रहा है, बल्कि गैरकानूनी सभा के सदस्य के रूप में उसकी सक्रिय भागीदारी भी स्थापित करने में सक्षम रहा है। हो सकता है कि उसने मृतक पर बम नहीं फेंका हो, लेकिन इससे वह गैरकानूनी सभा का सदस्य होना नहीं रुक जाता, जैसा कि आईपीसी की धारा 149 के दायरे में समझा जाता है और सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकालने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए सभी अभियुक्तों ने एक गैरकानूनी सभा का गठन किया था और मृतक पर हमला करना उनका सामान्य उद्देश्य था, जिसने खुद को लगी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। इस प्रकार विश्लेषण करने पर, प्रस्तुतीकरण पूर्ण महत्वहीनता के दायरे में प्रवेश करता है।

27. इस समय, हम अभियुक्त की इस दलील से निपटने के लिए बाध्य हैं कि बाबूलाल को मृतक के घर में कैद किया गया था और यही घटना की उत्पत्ति का कारक था। सबूतों की जांच करने पर पता चला कि आरोपी मंगल सिंह और बाबूलाल को मौके

पर ही पकड़ लिया गया और सिरिया के घर में बंद कर दिया गया, जहां से पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में बाबूलाल की मौत हो गई। उच्च न्यायालय ने सबूतों की जांच में पाया कि रिकॉर्ड पर यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि आरोपी व्यक्ति हमलावर थे और वे ही घटना स्थल पर पहुंचे और मंगल ने गालियां दीं और हाथ से बने बम को मृतक श्रीराम की छाती पर फेंक दिया। इसके बाद साक्ष्यों से पता चलता है कि मंगल और बाबूलाल को चोटें आईं। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने यह मानकर निर्देशित हुआ है कि खुली लड़ाई हुई थी। उक्त निष्कर्ष स्पष्ट रूप से गलत है क्योंकि अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्थापित किया है कि आरोपी व्यक्ति हमलावर थे। बमबाजी की घटना के बाद पथराव हुआ और बंधक बनाया गया। आरोपी ही घातक हथियारों से लैस होकर आए थे और मंगल ने ही मृतक के सीने पर बम सिर्फ इसलिए फेंक दिया, क्योंकि उसने गाली-गलौज करने का विरोध किया था। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने इस साक्ष्य पर ध्यान देने के बाद कि मंगल और बाबूलाल को एक कमरे में बंद कर दिया था, राय दी थी कि खुली लड़ाई हुई थी। उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों की पुनरावलोकन और विश्लेषण पर पाया कि आरोपी व्यक्ति हमलावर थे। इसके अलावा, जैसा कि अभियोजन की पूरी कहानी से पता चलता है, आरोपी व्यक्ति घातक हथियारों से लैस होकर मृतक के घर गए और गंदी भाषा में गालियां दीं और विरोध करने पर, उनमें से एक मंगल सिंह ने पूर्व निर्धारित मन से मृतक के सीने पर बम फेंक दिया। उपरोक्त सबूतों के संबंध में, हम उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत हैं कि यह एक ऐसा मामला है जहां अपीलकर्ता आईपीसी की धारा 149 की सहायता से धारा 302 के तहत दोषी ठहराया जाना चाहिए।

28. प्रस्तुतीकरण का एक अन्य अंग जो श्री शर्मा द्वारा प्रतिपादित किया गया है वह यह है कि अभियोजन पक्ष ने जानबूझकर अन्य स्वतंत्र भौतिक गवाहों की जांच नहीं की है जो घटनास्थल पर मौजूद थे और इसलिए, अभियोजन का पूरा मामला

अस्वीकार्य हो जाता है। इस संदर्भ में, ए.पी. राज्य बनाम ज्ञान चंद[22] में जो कहा गया है उसका संदर्भ लेना लाभदायक होगा। उक्त मामले में तीन जजों की बेंच ने राय दी है कि:-

> "14. ... किसी महत्वपूर्ण गवाह की जांच न करना, रिकॉर्ड पर उपलब्ध गवाही के महत्व को खारिज करने का गणितीय सूत्र नहीं है, चाहे वह कितनी भी स्वाभाविक, भरोसेमंद और ठोस क्यों न हो। अभियोजन पक्ष के खिलाफ लगाए गए एक महत्वपूर्ण गवाह को अदालत में रोके रखने के आरोप की प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में जांच की जानी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या गवाह अदालत में जांच के लिए उपलब्ध हैं और फिर भी अभियोजन पक्ष द्वारा उन्हें रोका गया है।"

इसमें आगे यह निर्णय दिया गया है कि न्यायालय को पहले रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों की विश्वसनीयता पर विचार करना और उसका आकलन करना आवश्यक है और यदि न्यायालय को लगता है कि प्रस्तुत किए गए साक्ष्य विश्वसनीयता के योग्य हैं, तो गवाही को स्वीकार किया जाना चाहिए और उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, हालांकि अन्य गवाह भी उपलब्ध हो सकते हैं, जिनकी भी जांच की जा सकती थी, लेकिन जांच नहीं की गई। तखाजी हीराजी बनाम ठाकोर कुबेरसिंग चमनसिंह[23] में, यह राय दी गई है कि यदि भौतिक गवाह, जो घटना की उत्पत्ति या अभियोजन पक्ष के मामले के एक अनिवार्य हिस्से को उजागर करता है, को अन्यथा आश्वस्त रूप से सामने नहीं लाया जाता है, या जहां कोई अंतर है या अभियोजन पक्ष के मामले में कमज़ोरी जिसे एक गवाह की जांच करके पूरा किया जा सकता था या ठीक किया जा सकता था, हालांकि उपलब्ध होने के बावजूद उसकी जांच नहीं की गई है, अभियोजन पक्ष के मामले को कमी से ग्रस्त कहा जा सकता है और इस तरह के महत्वपूर्ण गवाह को रोकना अदालत को अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य करेगा, लेकिन

अगर ज़बरदस्त साक्ष्य उपलब्ध है और जिस पर भरोसा किया जा सकता है, तो ऐसे अन्य गवाहों से पूछताछ न करना सार्थक नहीं हो सकता है। इसी तरह, दहारी बनाम यूपी राज्य[24] में, भौतिक गवाहों की गैर-परीक्षा के मुद्दे पर विचार करते हुए, यह संक्षेप में व्यक्त किया गया है कि जब गवाह ही एकमात्र सक्षम गवाह नहीं है, जो तथ्यात्मक स्कोर को सही ढंग से समझाने में पूरी तरह से सक्षम होगा और अभियोजन चिकित्सीय साक्ष्य और अन्य विश्वसनीय गवाहों की गवाही के आधार पर पूरी तरह से पुष्टि करता है, अभियोजन पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना अनुचित होगा।

29. वर्तमान मामले में, गवाह, जैसा कि उच्च न्यायालय ने पाया है और हमारे पास असहमत होने का कोई कारण नहीं है, विश्वसनीय हैं और अपने संस्करण पर कायम हैं और अडिग रहे हैं। उन्होंने घटना की उत्पत्ति, अपराध में आरोपी व्यक्तियों की भागीदारी और संलिप्तता और मृतक और उनमें से प्रत्येक को लगी चोटों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया है। इसलिए, किसी भी अन्य गवाह से पूछताछ न करना, जो घटना स्थल पर उपलब्ध हो सकता था, अभियोजन पक्ष के मामले को अस्वीकार्य नहीं बनाएगा। इस आधार पर, अभियोजन पक्ष के मामले को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, हम अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतीकरण को अस्वीकार करने के लिए बाध्य हैं।

30. अंतिम निष्कर्ष में, हम मानते हैं कि अभियोजन पक्ष के गवाहों, जो घटना के स्वाभाविक गवाह हैं, के साक्ष्य में छोटी विसंगतियों और चूक पर जोर देना और अप्रासंगिक पहलुओं पर जोर देना और अंततः दोषमुक्ति को रिकॉर्ड करना कल्पना की किसी भी विस्तार से, विद्वान परीक्षण न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किया गया एक स्वीकार्य या संभावित दृष्टिकोण नहीं माना जा सकता है और, इसलिए, हमारा दृढ़ मत है कि दोषसिद्धि में से किसी एक दोषी को बरी करने के निर्णय को पलटना उच्च न्यायालय के लिए उचित है।

31. परिणामस्वरूप, अपील, किसी भी योग्यता से रहित होने के कारण, खारिज करने का मार्ग प्रशस्त करती है, और हम ऐसा निर्देश देते हैं।

अपील खारिज की गई।

देविका गुजराल

---

[1] (2009) 10 एससीसी 636

[2] (2006) 10 एससीसी 313

[3] (2009) 10 एससीसी 636

[4] (2010) 12 एससीसी 59

[5] (2003) 11 एससीसी 271

[6] (2012) 6 एससीसी 297

[7] (2014) 5 एससीसी 154

[8] एआईआर 1953 एससी 364

[9] एआईआर 1952 एससी 54

[10] (1981) 3 एससीसी 675

[11] (1974) 3 एससीसी 277

[12] (2010) 10 एससीसी 259

[13] (1973) 3 एससीसी 881

[14] (1975) 3 एससीसी 311

[15] (2009) 10 एससीसी 477

[16] (2010) 6 एससीसी 673

[17] (2009) 9 एससीसी 719

[18] एआईआर 1956 एससी 181

[19] एआईआर 1965 एससी 202

[20] (2004) 12 एससीसी 414

[21] (2011) 9 एससीसी 257

[22] (2001) 6 एससीसी 71

[23] (2011) 9 एससीसी 257

[24] (2012) 10 एससीसी 256

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता अनिल जोशी द्वारा किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।